	Last year of	
	1st Five-year Plan i.e., (1955-56)	3rd Five-year Plan i.e., (1965-66)
Route kilometrage	55,011	58,899
Total Track-kilometrage	78,233	92,474
No. of goods wagons (in Units)	240,756	370,019
No. of Engines :		
Steam	9,026	10,613
Diesel	67	727
Electric	79	403
Earnings from goods traffic moved by the railways excluding wharfages, demurrage charges etc. (Crores)	Rs. 177·4	Rs. 452·4

परिपैती से जामातार के लिए लाइन

2701. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिपैती से दुमका होकर जामातार या किउल-आसनसोल लाइन पर एक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव कभी सरकार के विचाराधीन रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन खनिजों की ढुलाई के लिये और इस पिछड़े आदिवासी क्षेत्र में अधिक आवागमन सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये वहां पर एक रेलवे लाइन बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) दुमका के रास्ते पिरपैन्ती और जमतारा के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और संसाधनों की अत्यन्त सीमित उपलब्धता के कारण इस समय रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Abstention from voting by electorate of Jhibi Archal

2702. SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Will th Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2698 on 6th December, 1977 regarding abstention from voting by electorate of Jhibi Archal in the last Parliamentary Election, and state whether Government have since collected information about their grievances and causes for such abstention;

(b) what steps have been taken by the Central Government so far as it lies in their power for meeting the grievances; and

(c) what guidelines, if any, have been given to the Government of West Bengal so far as the matter lies in their power?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH YADAV): (a) According to the information furnished by the Chief Electoral Officer, Government of West Bengal, no vote was polled in Jhibi Archal under Khargram police station of Murshidabad district comprising polling station numbers 75 to 83 in Khargram segment of 8 Jangipur Parliamentary Constituency. The reasons for absention of the voters concerned from voting are not known.

(b) and (c). Do not arise.

सूरत में एस्सो और इण्डेन गैस के उपभोक्ता

2703. **श्री छोटूभाई नायिक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) सूरत नगर और सूरत जिले में एस्सो और इण्डेन गैस के उपभोक्ताओं की

संख्या क्या है और नये उपभोक्ताओं की मांग कितनी है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के गैस के सिलिंडर नियमित रूप से नहीं मिलते; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने और गैस सिलिंडरों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं और नये उपभोक्ताओं की मांग कब तक पूरी की जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:—

क्षेत्र	कुकिंग गैस के उपभोक्ताओं की संख्या	
	इंडियन आयल कारपोरेशन	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन (एस्सो की उत्तराधिकारी)
सूरत शहर	15,250 (लगभग)	13,360
सूरत जिला (सूरत शहर को छोड़कर)	सूरत शहर के बाहर के क्षेत्रों में एल०पी०जी० का विपणन नहीं होता	9,000 (लगभग)

सम्पूर्ण सूरत जिले में कुकिंग गैस के लिए उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान लगभग 54,000 है :

(ख) और (ग) सितम्बर 1977 से दिसम्बर 1977 के दौरान सूरत क्षेत्र में, एल०पी०जी० की सीमित उपलब्धता के कारण, सिलिंडर रीफिलन की सप्लाई में कमी की गयी थी। अक्टूबर, नवम्बर, 1977 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी के पुनः कार्याम्भ करने के बाद, एच०पी० सी० रिफाइनरी पर कैटालिटिक डीवोटिल नेफिंग प्रोजेक्ट आरम्भ होने के बाद, सूरत क्षेत्र में एल०पी०जी० की उपलब्धता में सुधार हुआ। जब कि देश में वर्तमान उपभोक्ताओं की रीफिल की जरूरतें सामान्यतया पूरी हो रही हैं। देश में नये गैस कनेक्शन की मांग, आजकल एल०पी०जी० के शोधन शालाओं के उत्पादन की उपलब्धता से बहुत अधिक है। अगले दो से तीन वर्षों में उत्पाद के सुधरने की आशा है और तभी उपभोक्ताओं के नाम पंजीकृत करना भी संभव हो सकेगा।

बुक स्टाल का ठेका

2704. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ए०एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी बुक स्टाल के ठेके के लिये सरकार को 2½ प्रतिशत स्वामित्व अदा करती है,

(ख) यदि हां, तो क्या बुक स्टाल पर काम कर रहे कर्मचारी उसी ठेके के लिये 5 प्रतिशत स्वामित्व की अदायगी करने को तैयार है, और

(ग) यदि हां, तो बुक स्टाल का ठेका उनको किस कारण से नहीं दिया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) और (ग). छोटे-मोटे बुक स्टाल ठेकेदारों को छोड़कर, जो निम्नदर पर एकमुश्त लाइसेंस फीस का भुगतान करते हैं, अन्य बुक स्टाल ठेकेदारों द्वारा कुल बिक्री पर 2½ प्रतिशत की दर से रायल्टी का भी भुगतान किया जाता है। चूंकि ए०एच० व्हीलर एण्ड कं० और अन्य दो बड़े बुक स्टाल ठेकेदारों का ठेका 31-12-84 तक वैध